



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्ल्यू.बी.-अ.-28082024-256703
CG-WB-E-28082024-256703

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3319]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 28, 2024/भाद्र 6, 1946

No. 3319]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 28, 2024/BHADRA 6, 1946

वस्त्र मंत्रालय

(पटसन आयुक्त का कार्यालय)

आदेश

कोलकाता, 27 अगस्त, 2024

का.आ. 3636(अ).—कथित मिल कंपनी अर्थात ओलिसा रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड पर लगाए गए आरोप, लिमिटेड ने दिनांक 15 दिसंबर, 2023 के कारण बताओ पत्र क्रमांक जूट(टी)-6/1/397/23-आई(ई) के माध्यम से लगातार अवसरों पर सुनवाई की है, सुनवाई की अंतिम तिथि 1 अप्रैल, 2024 है, जिसमें सुनवाई पूरी हो चुकी है, मामला आदेश पारित करने के लिए सुरक्षित रखा गया।

पृष्ठभूमि: दिनांक 5 अक्टूबर, 2023 के पीसीएसओ संख्या HRHSKO51023PR28648 के माध्यम से, कथित मिल कंपनी को हरियाणा राज्य सरकार को आपूर्ति के लिए बी-टवील बारदानों की आपूर्ति हेतु थोक आदेश दिए गए थे। सांविधिक प्रावधानों के नियमानुसार, मिल के प्रतिनिधियों, निरीक्षण अभिकरणों अर्थात मेसर्स एस्केप्स और पटसन आयुक्त कार्यालय के अधिकारियों की उपस्थिति में, 5 और 6 दिसंबर 2023 को कथित मिल परिसर में निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित विसंगतियाँ पाई गई:-

“मिल प्रतिनिधियों एवं मेसर्स एस्केप्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की उपस्थिति में 46 विवादीत गांठों में से 3 गांठों को खोला गया एवं निम्नलिखित अवलोकन प्रस्तुत है।

क्रम सं.	गाठों की सं.	मंतव्य
1.	0038	i. बिना ब्रांड वाले बी-टवील बारदानें पाए गए जिसमें लाल रंग के दो चिह्न अंकित थे।
2.	0068	i. टाईप-ए बिना ब्रांड वाले बी-टवील बारदानें पाए गए ii. पंजाब सरकार के बी-टवील बारदानों में एकल नीले/ लाल और काले चिह्न पाए गए iii. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एवं हरियाणा सरकार के बी-टवील बारदानों में एकल नीले चिह्न पाए गए iv. छत्तीसगढ़ सरकार के बी-टवील बारदानों में एकल नीले/ लाल रंग के चिह्न पाए गए v. पश्चिम बंगाल सरकार के बी-टवील बारदानों में एकल नीले और काले चिह्न पाए गए vi. बिना ब्रांड वाले बारदानों में दोहरे लाल/ नीले एवं काले चिह्न पाए गए vii. भारत में निर्मित एवं अंबिका का मुद्रण वाले दोहरे लाल चिह्न वाले बी-टवील बारदानें पाए गए viii. हरियाणा सरकार के ब्रांड वाले (मिल का नाम- लडलो) दोहरे लाल चिह्न वाले बी-टवील बारदानें पाए गए
3.	0057	i. पश्चिम बंगाल, पंजाब एवं हरियाणा सरकार के बी-टवील बारदानों में एकल नीले चिह्न पाए गए

टीम ने 8 बी-टवील बैग्स [दो (02) गैर-ब्रांडेड बैग जिनमें दो लाल और एकल नीले पहचान चिह्न हैं और एक (01) टाईप-ए, तीन (03) ब्रांडेड बैग जिनमें पंजाब, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ सरकारों के नीले पहचान चिह्न एकत्र किए हैं, एक (01) बैग जिस पर हरियाणा सरकार (मिल का नाम - लडलो) की ब्रांडिंग है और एक (01) बैग अंबिका की छपाई और भारत में निर्मित] के हस्ताक्षर के साथ नमूने के रूप में ऊपर उल्लिखित 3 विवादित गांठें मिल प्रतिनिधि खोलें। मिल प्रतिनिधि के समक्ष 3 विवादित गांठें जिन्हें खोला गया था, उन्हें दोबारा पैक कर शील कर दिया गया (शील संख्या 4287601 से 4287606)।

आगे, पटसन आयुक्त के प्रतिनिधियों द्वारा पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 की प्रावधानों के अनुसार दिनांक 05.10.2023 की पीसीएसओ संख्या HRHSK051023OPR28648 के तहत हरियाणा सरकार के 150 गांठें जप्त किए गए। जप्त किए गए गांठों को जिम्मा से श्री सिताराम गांगुली, प्रबंधक फिनिशिंग एवं मेसर्स ओलिसा रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड के एसक्यूसी को सुपुर्द कर दिया गया। मिल कंपनी को यह सलाह दी गई कि जप्त किए गए गांठों को अलग और सुरक्षित स्थान पर रखा जाए एवं अप्रतियाशित स्थिति के सिवाय इन गांठों का उपयोग/बदलाव/प्रेषण न किया जाए (जिसे पटसन आयुक्त के कार्यालय को अविलंब सूचित कर दिया जाए)। जब तक कि पटसन आयुक्त के कार्यालय से कोई आगे की सूचना प्राप्त न हो जाए।”

तदनुसार, दिनांक 15 दिसंबर, 2023 के पत्र संख्या पटसन(टी)-6/1/397/23-I(ई) के तहत कथित मिल कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका उत्तर 19 दिसंबर, 2023 के पत्र के माध्यम से प्राप्त हुआ।

सुनवाई के दौरान जप्त किए गए बारदानों के विसंगतियों को दर्शाया गया, कार्रवाई पक्षकारों की उपस्थिति में सुनवाई के समय विभाग द्वारा कथित मिल कंपनी के विरुद्ध सबूत के रूप में उक्त बारदानों का इस्तेमाल किया गया था।

विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा कथित मिल कंपनी से प्राप्त कारण बताओ नोटिस के हवाले से यह रुख अपनाया गया कि मिल प्राधिकारी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और इसकी जिम्मेदारी कर्मचारियों पर डाली गई है।

दूसरी ओर कथित मिल कंपनी के प्रतिनिधि ने विभाग द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया, उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात पर जोर दिया कि विभाग उनके द्वारा दिए गए कारण बताओ नोटिस की व्याख्या करने में विफल रहा

है। उन्होंने बताया कि, कुछ बी-टवील बैग्स बहुत पहले प्रतिस्पर्धी बाजार में गुणवत्ता की जांच करने के लिए अलग-अलग फसल वर्षों की विभिन्न मिलों से लिए गए थे, यह कुछ कर्मचारियों की सरासर लापरवाही के कारण है कि बैग निरीक्षण लॉट के साथ मिश्रित हो गए। इसमें न तो कोई आपराधिक मंशा है और न ही अनुचित व्यवहार को बढ़ावा देने का कोई प्रयास है, अर्थात् भारी मात्रा में आपूर्ति के बीच, केवल कुछ बैग यदि गलत पाए जाते हैं तो किसी भी तरह से कथित मिल कंपनी के किसी भी गलत इरादे का उजागर नहीं होता है, क्योंकि जैसा कि आरोप लगाया गया है, कदाचार से कंपनी को मामूली लाभ मिलेगा जिसकी आवश्यकता नहीं है। सुनवाई के दौरान कथित मिल कंपनी के प्रतिनिधियों ने हालांकि स्वीकार किया कि उनकी ओर से लापरवाही हुई है, लेकिन लापरवाही से उनका व्यवसाय का अधिकार नहीं छीना जाना चाहिए, जो हजारों श्रमिकों को उनकी आजीविका देकर लाभान्वित कर रहा है।

विभाग ने कथित मिल कंपनी पर पीसीएसओ की रोक लगाने की प्रार्थना की और कथित मिल कंपनी ने उनकी साख और अनजाने में हुई अवहेलना को देखते हुए शिकायत को खारिज करने की प्रार्थना की।

सभी प्रस्तुतियाँ अभिलेखों में रखी गईं और सुनवाई की तारीखों की आरओपी के माध्यम से विचार-विमर्श किया गया, उक्त आरओपी को कार्यवाही के दौरान संबंधित पक्षों को वितरित किया गया।

निरीक्षण एजेंसी ESKAPS ने भी कार्यवाही के सभी पक्षों की उपस्थिति में इस निर्णायक प्राधिकारी के समक्ष गवाही दी, उन्होंने प्रस्तुत किया कि पीसीएसओ नंबर HRHSK051023OPR28648OPR28648 दिनांक 05.10.2023 के खिलाफ वितरण योग्य सामग्रियों का 5 दिसंबर, 2023 को निरीक्षण किया गया था, जिसमें 150 गांठें थी जिन्हें हरियाणा सरकार को भेजा जाना था। इन 150 गांठों में से 46 गांठें छेड़छाड़/टूटी हुई निरीक्षण सील और स्टिकर के साथ पाई गईं, जबकि गांठें अभी भी मिल कंपनी की निगरानी में थीं; छेड़छाड़ की गई गांठों के अंदर अलग-अलग फसल वर्ष और अलग-अलग खेप के बैग पाए गए (05.12.2023 को निरीक्षण के दौरान क्रमरहित रूप से खोली गई एवं 3 गांठों से छेड़छाड़ की गई) जो अस्वीकार्य थीं, और जैसा कि संकेत दिया गया है उन बोरियों को जब्त कर लिया गया था और जब्त किए गए नमूने बैगों को प्रदर्शित किया गया था सुनवाई के दौरान निरीक्षण एजेंसी के बयानों की पुष्टि हुई।

निरीक्षण एजेंसी के बयान को रिकॉर्ड में रखा गया है।

आदेश:- कथित मिल कंपनी द्वारा दिए गए कारण बताओ नोटिस का अवलोकन किया गया है, जब्त किए गए सामग्री और निरीक्षण एजेंसी के साथ-साथ विभाग के बयानों की पुष्टि की गई है, कथित मिल कंपनी के विरुद्ध आरोप स्थापित हो गए हैं, पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 का पालन करना होगा। इसलिए कानून के नियमानुसार, पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 के पैराग्राफ 8 (ए) को लागू करते हुए, मेसर्स ओलिसा रियलिटी प्रा. लिमिटेड को इस आदेश की तारीख से 3 महीने तक संभावित आधार पर पीसीएसओ प्रदान करने से रोक दिया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि, मेसर्स ओलिसा रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड को प्राप्त सभी आदेश, जो इस आदेश के पारित होने के समय मिल कंपनी द्वारा अभी तक प्रेषित नहीं किए गए हैं, उन्हें उचित समय में पूरा करना होगा, अन्यथा अलग से कार्यवाही होगी; यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि, इस विशेष मामले में निपटाए गए जो सामान दोषपूर्ण पाए जाते हैं, उन्हें इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक पखवाड़े के भीतर कंपनी की लागत पर बदला जाना है। पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 के पैराग्राफ 10 के अनुसार, मिल कंपनी को, यदि असहमत है, उचित फोरम के समक्ष अपील दायर करने की स्वतंत्रता दी गई है।

मामला निस्तारित हो गया है।

इस आदेश को अविलंब सभी आवश्यक पक्षों को वितरित किया जाए।

[फा. सं. जूट(टी)-6/1/178/जीएन(3)/2019-I(ई)]

मलय चंदन चक्रवर्ती, पटसन आयुक्त

MINISTRY OF TEXTILES
(Office of the Jute Commissioner)

ORDER

Kolkata, the 27th August, 2024

S.O. 3636(E).—The allegations levelled against the alleged mill company i.e. Olisa Reality Pvt. Ltd. vide show cause letter No. Jute(T)-6/1/397/23-I(E) dated 15th December, 2023, has been heard on successive occasions, the final date of hearing being 1st April, 2024, wherein the hearing stood concluded, the matter was reserved for passing order.

BACKGROUND:- Vide PCSO being numbered HRHSKO510230PR28648 dated 5th October, 2023, the alleged mill company was given bulk orders for supply of B-Twill Jute Bags for supply to the State Government of Haryana. In terms with statutory provisions, an inspection was held at the alleged mill premises on 5th & 6th December 2023, in presence of the Mill's representatives', inspection agency i.e. M/s Eskaps and officials from the Office of Jute Commissioner. The said inspection revealed following anomalies:-

“The inspection team opened 3 bales out of 46 disputed bales in presence of mill representative & M/s Eskaps India Pvt. Ltd and following observations have been made-

Sl. No.	Bale No.	Observations
1	0038	i. Found unbranded B-Twill bags having two red identification marks.
2	0068	i. Type-A unbranded B-Twill bags have been found. ii. B-Twill bags of Govt. of Punjab having single Blue / Red & Black identification marks have been found. iii. B-Twill bags of Govt. of UP, MP, Uttarakhand & Haryana having single Blue identification marks have been found. iv. B-Twill bags of Govt. of Chhattisgarh having single Blue / Red identification marks have been found. v. B-Twill bags of Govt. of West Bengal having single Blue & Black identification marks have been found. vi. Found unbranded B-Twill bags having two Red / Blue & Black identification marks. vii. B-Twill bags of having two Red identification marks have been found with printing of Ambica & Manufactured in India. viii. B-Twill bags of having two Red identification marks have been found with branding of Govt of Haryana (Mill Name – Ludlow)
3	0057	i. B-Twill bags of Govt. of West Bengal, Punjab & Haryana having single Blue identification marks have been found.

The team has collected the 8 B-Twill Bags [Two (02) unbranded bags having two red and single Blue identification marks and one (01) Type-A, three (03) branded bags having single blue identification marks of Govt of Punjab, MP and CG, one (01) bag having branding of Govt of Haryana (Mill Name–Ludlow) and one (01) bag printing of Ambica & Manufactured in India] from the 3 above mentioned opened disputed bales as sample along with the signature of mill representative. The 3 disputed bales, which were opened, were repacked and sealed (Seal No. 4287601 to 4287606) in presence of the mill representative.

Further, the representative from O/o the Jute Commissioner had seized the 150 bales of Govt. of Haryana (HSWC) under PCSO No. HRHSKO510230PR28648 dated 05.10.2023 as per the provision in Jute and Jute Textiles Control Order, 2016. The seized bales were handed over/ Zimma to Shri Sitaram Ganguli, Manager Finishing & SQC of M/s Olisa Reality Pvt. Ltd. The mill company has been advised to keep the seized bales segregated in safe custody and not to use/shift/delivered except under force majeure conditions (which should be immediately informed to the O/o the Jute Commissioner) until further instructions received from office of the Jute Commissioner.”

Accordingly, a show cause notice was served on the alleged mill company vide letter No Jute(T)-6/1/397/23-I(E) dated 15th December, 2023, reply thereto was received on 19th December, 2023 vide letter No. Nil.

The seized jute bags depicting anomalies were kept as exhibits during the course of hearing, the said bags were used as evidence against the alleged mill company, by the department at the time of hearing, in presence of parties' to the proceedings.

The stand taken by the representatives from the department, quoting from the reply to show cause received from the alleged mill company, that the mill authority has admitted the guilt and the onus was thrashed upon employees.

On the other hand the representative from the alleged mill company denied the point of admission being levelled by the department against them, they categorically emphasized that department has failed to interpret the reply against the show cause given by them. They pointed out that, few B-Twill bags long back were taken from different mills of different crop years, only to check the quality in a competitive market, it is by sheer negligence of few employees that the bags got mixed up with the inspecting lot, there is neither any *mens rea* nor any attempt as such to perpetrate unfair practice, i.e. amongst huge bulk supply, only few bags if are found to be not in order in no way discloses any *mala fide* intention of the alleged mill company, since the malpractice as alleged, will reap miniscule benefit which is not called for. The representatives from the alleged mill company during the course of hearing however admitted that there is negligence on their part but that negligence should not take away the right of them to business, which is practically benefiting thousands of workers by giving them their livelihood.

The department prayed for debarment of PCSO on the alleged mill company and the alleged Mill company prayed for, dismissal of the complaint considering their reputation and unintentional negligence.

All the submissions were kept on record and deliberated through ROP of hearing dates, the said ROP (s) were circulated to the parties' to the proceedings in course .

The inspection agency ESKAPS also deposed before this adjudicating authority in presence of all the parties' to the proceedings, they submitted that amongst the deliverable material against PCSO No. HRHSK051023OPR28648 dated 05.10.2023 inspection was conducted on 5th December, 2023, in which there were a lot of 150 bales about to be dispatched to Govt. of Haryana. Out of these 150 bales, 46 bales were found with tampered/ broken inspection seals and stickers while the bales were still in the custody of the mill company; bags of different crop year and of different consignees were found inside the tampered bales (3 tampered bales opened at random during inspection on 05.12.2023) which were unacceptable, and those bags as has been indicated were seized and sample seized bags were exhibited in course of hearing which corroborated the statements of the inspection agency.

The deposition of Inspection Agency has been kept on record.

ORDER:- The reply to the show cause given by the alleged mill company has been perused, the seized goods and the statements of the inspection agency, as well as the department, has been corroborated, the allegations against the alleged mill company stands established, the provisions of the Jute & Jute Textile Control Order, 2016, has to be followed. Therefore, in strict terms of the statute and invoking paragraph 8 (a) of the Jute & Jute Textiles Control Order, 2016, M/s Olisa Reality Pvt. Ltd. is debarred from being granted with PCSO on prospective basis from the date of this order to 3 months. It is made clear that, all the orders received by the M/s Olisa Reality Pvt. Ltd., which are yet to be dispatched by the mill company at the time of passing of this order, has to be fulfilled by them in proper time, else separate proceedings will follow; it is further made clear that, the goods which are found to be defective, dealt in this particular case, are to be replaced at the cost of the company within a fortnight from the date of receipt of this order. Liberty is given to the mill company, if aggrieved, to file appeal before appropriate forum in terms with paragraph 10 of the Jute & Jute Textiles Control Order, 2016.

The matter is disposed.

Let this order be circulated forthwith, to all necessary parties'.

[F. No. Jute(T)-6/1/178/GN(3)/2019-I(E)]

MOLOY CHANDAN CHAKRABORTTY, Jute Commissioner